सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार संबंधी समिति

*534. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन में कार्यरत रूग्ण उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और उस समिति के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन के आधार पर कतिपय इकाइयों के पुनरुद्धार की योजनायें भी तैयार की हैं; और

(च) यदि हां, तो कुल, रूग्ण इकाइयों में से कितनी और कौन-कौन सी इकाइयों को प्रथम चरण में पुनरुद्धार के लिए चुना गया है और प्रथम चरण पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुयार्डो फेलेरियो): (क) से (च) सरकार ने 16 जून, 1994 को एक तकनीकी समिति का इस बात की जांच पड़ताल के लिए गठन किया था कि क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) जो उर्वरक क्षेत्र में रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप I और II एककों का समस्याग्रस्त उपस्करों के नवीकरण/प्रतिस्थापन पर कुछ निवेश करके प्रचालन किया जा सकता है। समिति का गठन निम्नानुसार था:

(1) डा० जी० बी० पुरोहित सलाहकार (उर्वरक) उर्वरक विभाग

(2) श्री अली शाहीद वरिष्ठ प्रबन्धक, पी डी आई एल, सिन्दरी

(3) श्री ए० के सिंह प्रबन्धक (प्रक्रिया इंजीनियरिंग) इफको, आंवला

सरकार के समक्ष, 19.7.1994 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में तकनीकी समिति ने उपरोक्त एककों के प्रचालनों को जारी रखने के लिए आवश्यक अन्य उपचारी उपायों के साथ समस्यापरक उपस्करों तथा प्रतिस्थापन मरम्मत और संशोधन हेतु दुर्बल क्षेत्रों की शिनाख्त की थी। समिति ने 263.18 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया था और उपरोक्त एककों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्ट्रीम दिवसों और उत्पादन क्षमताओं का मूल्यांकन भी किया था। तथापि समिति ने बताया था कि एच एफ सी के पास वृहत योजना और गैर योजना ऋण, संचित ब्याज भार तथा निगम ऋण बकाया थे और इन दायित्वों को भविष्य में सृजित रोकड़ से पूरा नहीं किया जा सकता जिनकी उपर्युक्त सीमा तक निवेश करने तथा एककों की क्षमताओं की दर को कम निर्धारित करने के पश्चात भी प्राप्त होने की आशा है।

तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी हाल ही में एच एफ सी के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार की है जिसमें सिद्धान्त रूप में, पुनरुद्धार के माध्यम से इसके बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों के पुनर्वास तथा हल्दिया उर्वरक परियोजना को इस तथ्य के मद्देनज़र कि इस परियोजना का पुनरुद्धार व्यवहार्य नहीं है, किसी और को देना परिकल्पित है। पुनरुद्धार योजना में पूंजीगत पुनर्संरचना और अन्य वित्तीय राहतों के अलावा 464.93 करोड़ रुपए के नये निवेश की परिकल्पना की गयी है। इन एककों के पुनरुद्धार के लिए निधियों के संबंध में अभी तक व्यवस्था नहीं की गयी है।

Land under Central/State farms in Uttar Pradesh

*535 SHRI AAS MOHAMMAD:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total area of land under the Central State Farms in Uttar Pradesh;

(b) the area of land being utilised for production of seeds of various foodgrains; and

(c) the quantum of seeds produced in these farms during 1993-94?